Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 29-11-2005

Participants : Sangwan Shri Kishan Singh

>

Title : Need for Central intervention in the alleged irregularities in procurement of paddy in Haryana and other parts of the country.

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : महोदय, लगभग एक महीने से देश में पैडी की फसल मार्केट में आई हुई है। भारत सरकार ने पैडी की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की थी, वह देश की कुल फसल के दस प्रतिशत के लिए है। वह सपोर्ट प्राइस भी किसानों को नहीं मिल रहा है। 90 प्रतिशत पैडी की जो फसल है, वह बासमती है, शरबती है और पुच्छल है जिसका पूरे देश के मार्केट में न कोई सरकारी और न कोई प्राइवेट ग्राहक है। किसान बुरी तरह से लुट रहा है, पिट रहा है। सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। पिछले वर्ा की तुलना में इस बार किसान को उसकी पैडी और चावल का रेट छः-सात सौ रुपये प्रति क्विंटल कम मिल रहा है। एक तरफ हम किसान की समस्याओं के लिए बहस करते हैं और दूसरी तरफ जब फसल पककर मार्केट में आई है तो उसका कोई ग्राहक नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे किस्म की पैडी की फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। डीज़ल और खेती के दूसरे इनपुट्स की कीमतें बढ़ रही हैं। किसान की फसल पिट रही है। इस कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए, वह उसके मिनिमम प्राफिट के हिसाब से होना चाहिए। सभी किस्मों की फसलों को को सरकार खरीदे। केवल दस परसेंट के लिए प्राइस तय कर दिया, लेकिन 90 प्रतिशत फसल देश में पिट रही है। सारे देश के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों की सुनवाई के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के कृाि मंत्रालय से निवेदन है कि तुरंत पूरे देश की रिपोर्ट मंगवाएं और किसानों को उनकी फसल का पूरा भा व दिया जाए वरना किसान बरबाद हो जाएंगे।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Speaker, Sir, let me associate myself with the submission made by Shri Sangwan.

MR. SPEAKER: I am sorry, you have not given a notice on this issue.